National Research Journal of Social Sciences
Volume-10, Issue-1, January-June 2025
PP: 157-167
ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

जाति पहचान से विकास विमर्श तक छपरा में मतदान-निर्णय के बदलते आधार

गौरव कुमार

जेआरएफ, विश्विद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्विद्यालय, छपरा

सार

छपरा (सारण) की चुनावी राजनीति को लंबे समय तक जाति-आधारित सामाजिक गठबंधनों, स्थानीय नेतृत्व-प्रतिस्पर्धा और दल-प्रतीकों के परंपरागत अर्थों से समझा गया है। किंतु हाल के वर्षों में मतदान-निर्णय की भाषा में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखता है, जहाँ 'कौन-सी जाति किसके साथ है' के समानांतर 'कौन-सा काम हुआ, कौन-सी सुविधा मिली, और किससे रोज़गार व आजीविका की आशा बढ़ी' जैसे विकास-केन्द्रित मानदंड अधिक मुखर हुए हैं। यह अध्ययन छपरा विधानसभा के 2020 के आधिकारिक परिणामों, सारण लोकसभा के 2024 के आधिकारिक परिणामों, सारण जिले के जनसांख्यिकीय व शैक्षिक संकेतकों, तथा बिहार 2020 के मतदानोत्तर सर्वेक्षण (लोकनीति-सीएसडीएस) में दर्ज मुद्दा-प्राथमिकताओं को आधार बनाकर मतदान-तर्क के पुनर्संयोजन का विश्लेषण करता है। निष्कर्ष यह है कि 'पहचान' और 'विकास' अब परस्पर प्रतिस्थापन की शून्य-राशि धारणा में नहीं, बल्कि एक मिश्रित निर्णय-ढाँचे में सह-अस्तित्व रखते हैं। पहचान समूह-विश्वास, प्रतिनिधित्व और नेटवर्क-राजनीति का आधार देती है, जबकि विकास, सेवाप्राप्ति, कल्याणकारी लाभ और रोजगार-संबंधी आकांक्षाएँ निर्णय के निकटवर्ती मानक बनती हैं। साथ ही, कड़ी प्रतिस्पर्धा और कम जीत-अंतर की स्थितियों में स्थानीय प्रत्याशी की विश्वसनीयता, योजनाओं की वास्तविक डिलीवरी, शहरी-ग्रामीण सेवा-अंतर, प्रवासन से जुड़ी आय-अस्थिरता, और डिजिटल सूचना-परिवेश मतदाता की गणना को और संवेदनशील बनाते हैं। यह बदलाव बताता है कि मतदाता हित, सम्मान और अवसर को एक साथ तौलता है। इस प्रकार छपरा में चुनावी विकल्प एक संकर तर्क से संचालित होता है, जिसमें सामाजिक पहचान और शासन-प्रदर्शन साथ-साथ राजनीतिक वैधता का निर्माण करते हैं।

कुंजी शब्द: छपरा, सारण, मतदान-निर्णय, जाति, विकास, कल्याणकारी राज्य, स्थानीय प्रतिस्पर्धा, बिहार चुनाव

भूमिका

छपरा की राजनीति को केवल जाति-समूहों के अंकगणित से समझना अब अपर्याप्त होता जा रहा है, क्योंकि मतदाता के सामने निर्णय का "इनपुट सेट" विस्तृत हुआ है। एक ओर, सामाजिक पहचानें आज भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सुरक्षा-बोध, सम्मान, और संसाधन-प्राप्ति की अपेक्षाओं से जुड़ी हैं; दूसरी ओर, रोज़गार, महँगाई, सार्वजनिक सेवाएँ, सड़क-बिजली, शिक्षा-

© Copyright @ Authors

स्वास्थ्य, और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच जैसे मुद्दे मतदान के व्यावहारिक तर्क में अधिक प्रमुखता लेते दिखते हैं। बिहार 2020 के मतदानोत्तर सर्वेक्षण में "सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा" के रूप में "विकास" का अनुपात 36.7% और "बेरोज़गारी/नौकरी" का अनुपात 21.0% दर्ज होना, तथा "केवल सुशासन-विकास" बनाम "जाति-समुदाय ही असली मुद्दा" वाले द्विविकल्प में 67.1% का पहले कथन के पक्ष में जाना, इसी संरचनात्मक बदलाव की दिशा बताता है [1]। यह संकेत छपरा जैसे जिलास्तरीय केन्द्रों पर और अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है, जहाँ ग्रामीण-शहरी, कृषि-गैरकृषि, प्रवासन-आधारित आय, तथा सेवाओं की उपलब्धता, ये सभी एक साथ मतदान-निर्णय के अनुभव-आधारित प्रमाण बनते हैं।

इस शोध का केन्द्रीय प्रश्न यह है कि छपरा में "जाति पहचान" से "विकास विमर्श" की ओर बदलाव को किस तरह समझा जाए। क्या यह पूर्ण विस्थापन है, या फिर एक नई तरह की संकर राजनीति है जहाँ पहचान-आधारित अपेक्षाएँ विकास-आधारित प्रदर्शन के साथ जुड़कर निर्णय बनाती हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह लेख चुनाव परिणामों के ठोस आँकड़ों [2], [3], जिला-स्तरीय सामाजिक संकेतकों [4], [5], तथा सर्वेक्षण-आधारित राजनीतिक अभिमत [1] को एक साथ रखकर व्याख्या प्रस्तुत करता है।

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और साहित्य-समीक्षा

भारतीय चुनावी राजनीति में "पहचान" का अर्थ केवल जाति-नाम नहीं होता; वह एक सामाजिक नेटवर्क, संसाधन वितरण की अपेक्षा, सुरक्षा/सम्मान की मांग, तथा राज्य से संबंध बनाने की रणनीति भी होती है। पहचान-आधारित दल-व्यवस्था के अध्ययन बताते हैं कि जब सामाजिक समूहों के पास प्रतिनिधित्व के माध्यम से "विश्वसनीय प्रतिबद्धता" का संकेत मिलता है, तो वे राजनीतिक गठबंधन बनाते हैं और टिकाते हैं [6]। यह परिप्रेक्ष्य बिहार में विशेष रूप से प्रासंगिक रहा है, जहाँ सामाजिक न्याय की राजनीति ने प्रतिनिधित्व के प्रश्न को राज्य-नीति के केन्द्र में लाया [7]।

परंतु 2000 के बाद बिहार में शासन-प्रदर्शन, आधारभूत संरचना, सार्वजनिक सेवाओं, और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार ने मतदाता-राज्य संबंध की भाषा को बदलने में भूमिका निभाई। पहचान की राजनीति, जो पहले मुख्यतः प्रतीकात्मकता और समूह-प्रतिनिधित्व की राजनीति थी, धीरे-धीरे "लाभ-आधारित नागरिकता" और "दावेदारी" (एंटाइटलमेंट) की राजनीति से जुड़ती गई। यहाँ विकास-विमर्श को "पहचान का विकल्प" नहीं बल्कि "पहचान के भीतर प्रदर्शन का मानक" समझना अधिक उपयुक्त है। इसी कारण अनेक अध्ययनों में यह तर्क उभरता है कि भारतीय लोकतंत्र में विचारधारा, पहचान और प्रदर्शन—तीनों मतदाता के निर्णय में अलग-अलग भार के साथ मौजूद रहते हैं [8]।

छपरा के संदर्भ में यह परिवर्तन इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि जिले की जनसांख्यिकी, शिक्षा की स्थिति, और रोजगार-आकांक्षाओं का दबाव राजनीतिक अपेक्षाओं को रूपांतरित करता है। श्रम बाज़ार और रोजगार संरचना पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण यह दिखाते हैं कि रोजगार-

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

अनिश्चितता और कार्य-गुणवत्ता (अनौपचारिकता) जैसे कारक राजनीतिक प्राथमिकताओं में "नौकरी/भर्ती/उद्योग" को प्रमुख मुद्दा बनाते हैं [9]। यही प्रवृत्ति बिहार 2020 के सर्वेक्षण निष्कर्षों में "बेरोज़गारी/नौकरी" के उच्च अनुपात के रूप में दिखती है [1]।

अनुसंधान-पद्धति और डेटा-स्रोत

यह अध्ययन बहु-स्रोत, व्याख्यात्मक-विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाता है। पहला स्रोत छपरा विधानसभा क्षेत्र का 2020 का आधिकारिक उम्मीदवार-वार मत-परिणाम है, जिसमें कुल वैध मत, शीर्ष प्रत्याशियों के मत, और जीत-हार का अंतर प्रत्यक्ष उपलब्ध है [2]। दूसरा स्रोत सारण लोकसभा क्षेत्र का 2024 का आधिकारिक विस्तृत परिणाम है, जिससे जिले/क्षेत्र की व्यापक राजनीतिक दिशा और प्रतिस्पर्धा की तीव्रता मापी जा सकती है [3]। तीसरा स्रोत सारण जिला प्रशासन के आधिकारिक जनसांख्यिकी और शिक्षा संकेतक हैं, जिनसे सामाजिक संदर्भ का मानकीकृत चित्र बनाया गया है [4], [5]। चौथा स्रोत लोकनीति-सीएसडीएस का बिहार 2020 मतदानोत्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदन है, जहाँ "मतदान के समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा", "विकास बनाम जाति" जैसे प्रश्नों के प्रतिशत-आधारित निष्कर्ष उपलब्ध हैं; साथ ही इसी सर्वेक्षण की पद्धति-सूचना से नमूना-प्रकृति और विश्वसनीयता की पृष्ठभूमि मिलती है [1], [10]।

इन स्रोतों के आधार पर लेख तीन स्तरों पर निष्कर्ष निकालता है। पहला, छपरा और सारण में प्रतिस्पर्धा का संख्यात्मक स्वरूप (मत-प्रतिशत, जीत-अंतर, "अन्य/नोटा" का आकार) निकाला गया। दूसरा, जिला-संदर्भ संकेतकों से विकास-विमर्श के सामाजिक आधार (साक्षरता, लिंगानुपात, जनघनत्व, शहरी निकाय) को जोड़ा गया [4], [5]। तीसरा, सर्वेक्षण-आधारित मुद्दा-प्राथमिकता से यह समझा गया कि मतदाता स्वयं किस भाषा में अपने निर्णय का तर्क प्रस्तुत करता है [1]।

छपरा-सारण का सामाजिक संदर्भ

सारण जिला प्रशासन के अनुसार जिले की जनसंख्या 3,951,862, क्षेत्रफल 2,641 वर्ग कि.मी., जनघनत्व 1,496 प्रति वर्ग कि.मी., तथा लिंगानुपात 954 दर्ज है [4]। साक्षरता के संदर्भ में औसत साक्षरता 65.96, पुरुष 77.03 और महिला 54.42 बताई गई है [4]। इसी जिले के शिक्षा पृष्ठ पर साक्षरता का एक अद्यतन प्रस्तुतीकरण (साक्षरता दर 67.17; पुरुष 77.89; महिला 55.13) भी उपलब्ध है, जो संकेत करता है कि शिक्षा संकेतकों पर स्थानीय प्रशासन निरंतर निगरानी रखता है [5]।

ये आँकड़े राजनीतिक अर्थ में इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अधिक जनघनत्व, अपेक्षाकृत कम महिला-साक्षरता, और शहरी-निकायों की उपस्थिति, ये सब मिलकर "सेवा वितरण" और "कल्याणकारी पहुँच" को मतदाता के रोज़मर्रा अनुभव का हिस्सा बनाते हैं। जब सड़क, बिजली, राशन, स्वास्थ्य सुविधा, या विद्यालय-व्यवस्था में बदलाव दिखता है, तो उसका श्रेय/दोष राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में तुरंत अनूदित होता है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के हिंदी संस्करण में राज्य स्तर पर सड़क-विस्तार, ऊर्जा-उपभोग में वृद्धि, और स्व-सहायता समूहों के विस्तार जैसे

© Copyright @ Authors

संकेतकों की चर्चा मिलती है, जो जिलास्तर पर “विकास के दावे” को पुष्ट करने हेतु राजनीतिक भाषा में प्रयुक्त होते हैं [11]। इसी व्यापक पृष्ठभूमि में एनएफएचएस-5 के संकेतक-सारांश यह रेखांकित करते हैं कि बिजली, बेहतर पेयजल और स्वच्छता पहुँच जैसे बुनियादी संकेतकों पर राज्यों में बढ़ोतरी हुई है; बिहार जैसे राज्यों में स्वच्छता कवरेज की चर्चा राजनीतिक विमर्श में लगातार दिखती है [12]।

तालिका 1: सारण जिले का चयनित जनसांख्यिकी-शिक्षा प्रोफ़ाइल (जनगणना 2011 आधारित प्रशासनिक प्रस्तुतीकरण)

संकेतक	मान
कुल जनसंख्या	3,951,862
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	2,641
जनघनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	1,496
लिंगानुपात	954
औसत साक्षरता	65.96
पुरुष साक्षरता	77.03
महिला साक्षरता	54.42

स्रोत: सारण जिला प्रशासन, जनसांख्यिकी पृष्ठ [4]।

इस तालिका के आधार पर यदि छपरा में मतदान-निर्णय की बदलती भाषा को समझें, तो स्पष्ट होता है कि “विकास” का अर्थ केवल बड़े परियोजना-घोषणाओं तक सीमित नहीं है। यह विद्यालयों की संख्या, सीखने के अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, और रोजगार-आकांक्षा जैसे जीवन-चक्र के मुद्दों से जुड़ा है। इसलिए विकास-विमर्श का उभार कई बार “पहचान” के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता, बल्कि पहचान-समूहों की भौतिक अपेक्षाओं को एक नई भाषा देता है।

छपरा विधानसभा 2020: प्रतिस्पर्धा का संख्यात्मक संकेत

छपरा विधानसभा क्षेत्र के 2020 के आधिकारिक परिणामों के अनुसार कुल मत 168,361 दर्ज हुए। शीर्ष प्रत्याशियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 75,710 मत और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को 68,939 मत प्राप्त हुए, जबकि शेष मत “अन्य/नोटा” श्रेणी में रहे [2]। यह संरचना दो बातों की ओर संकेत करती है। पहली, मुख्य मुकाबला द्विध्रुवीय है, पर निर्णायक बढ़त बहुत बड़ी नहीं है; दूसरी, “अन्य/नोटा” का आकार इतना है कि वह असंतोष, स्थानीय-उम्मीदवार प्रभाव, या रणनीतिक मतदान के अवसरों को इंगित करता है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

तालिका 2: छपरा विधानसभा 2020, शीर्ष प्रत्याशी, मत और अनुमानित मत-प्रतिशत

श्रेणी	मत	मत-प्रतिशत
भारतीय जनता पार्टी	75,710	44.97
राष्ट्रीय जनता दल	68,939	40.94
अन्य/नोटा	23,712	14.08
कुल	168,361	100.00

स्रोत: आधिकारिक विस्तृत परिणाम, छपरा विधानसभा 2020 [2]।

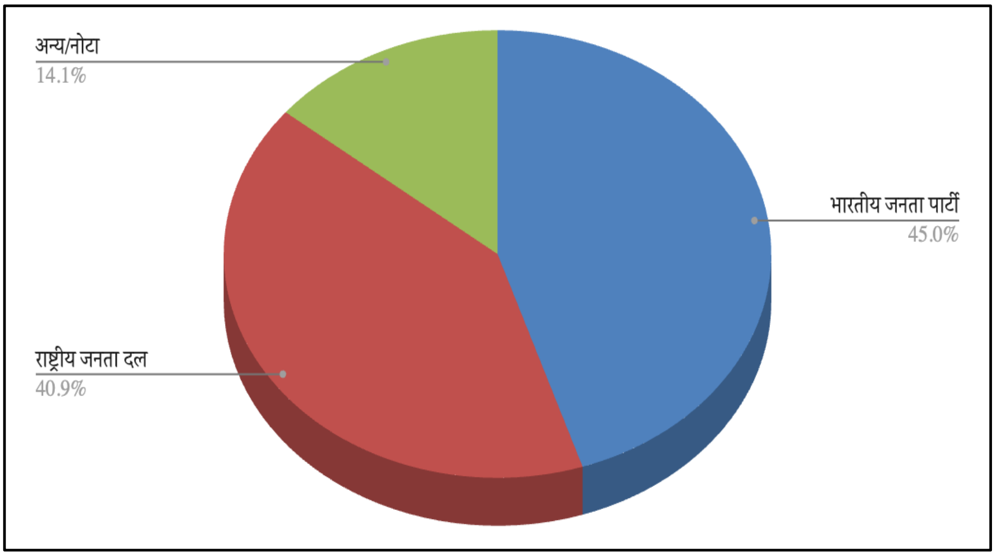

चित्र 1: छपरा विधानसभा 2020, शीर्ष प्रत्याशी, मत पाई चार्ट

यदि इन्हीं आँकड़ों से जीत-अंतर निकाला जाए, तो अंतर 6,771 मत बनता है। इतनी संकीर्ण प्रतिस्पर्धा में मतदाता के निर्णय-मानदंडों का सूक्ष्म बदलाव, जैसे "काम हुआ/नहीं हुआ", "नौकरी का भरोसा", "स्थानीय चेहरा" परिणाम को प्रभावित कर सकता है। यही वह बिंदु है जहाँ विकास-विमर्श और पहचान-विमर्श एक-दूसरे को काटने के बजाय एक-दूसरे के ऊपर बैठते हैं। पहचान समूह यह भी पूछते हैं कि "हमारे इलाके/टोले में किसने क्या कराया", और विकास का अनुभव भी अक्सर समूह-नेटवर्कों के माध्यम से राजनीतिक श्रेय में बदलता है।

सारण लोकसभा 2024: "विकास" बनाम "पहचान" का बड़ा फ्रेम

लोकसभा स्तर पर सारण (जिसका केन्द्र-न्याय छपरा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है) के 2024 के आधिकारिक विस्तृत परिणामों में कुल मत 1,021,508 दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 471,752 मत और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को 458,091 मत प्राप्त हुए; शेष मत

© Copyright @ Authors

अन्य/नोटा में रहे [3]। यहाँ जीत-अंतर 13,661 मत है, जो लोकसभा जैसी बड़ी इकाई में भी प्रतिस्पर्धा की तीव्रता दिखाता है।

तालिका 3: सारण लोकसभा 2024, शीर्ष प्रत्याशी, मत और अनुमानित मत-प्रतिशत

श्रेणी	मत	मत-प्रतिशत
भारतीय जनता पार्टी	471,752	46.18
राष्ट्रीय जनता दल	458,091	44.84
अन्य/नोटा	91,665	8.97
कुल	1,021,508	100.00

स्रोत: लोकसभा 2024 का आधिकारिक विस्तृत परिणाम (निर्वाचन क्षेत्र-वार) [3]।

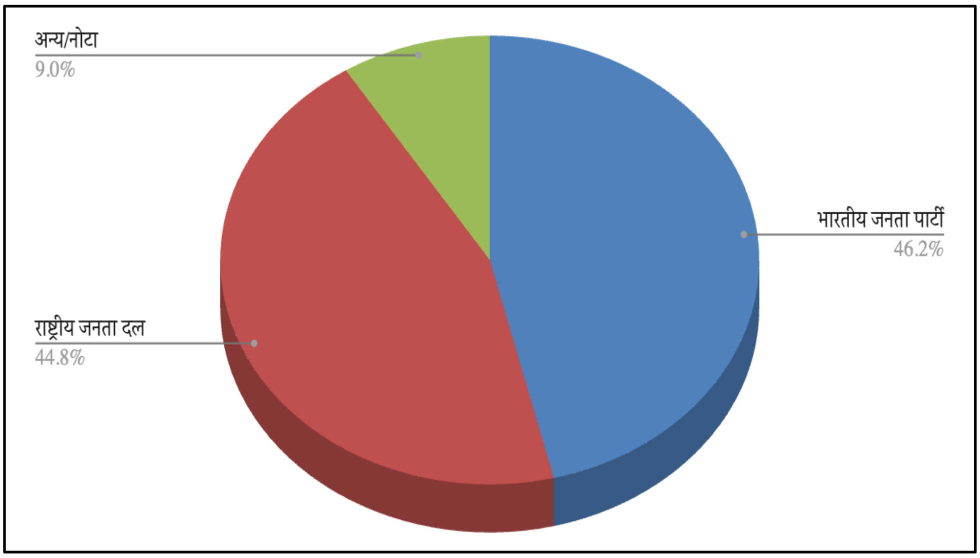

चित्र 2: सारण लोकसभा 2024, शीर्ष प्रत्याशी, मत पाई चार्ट

यह पैटर्न छपरा विधानसभा के 2020 के परिणामों से तुलनीय है: प्रतिस्पर्धा कड़ी है, और मामूली निर्णय-परिवर्तन बड़ी राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। इसी कारण दलों की रणनीति अब केवल स्थायी सामाजिक गठबंधनों पर नहीं, बल्कि "प्रदर्शन" के संकेतों—योजनाओं की डिलीवरी, स्थानीय मुद्दे, तथा रोजगार-आकांक्षाओं—पर भी निर्भर होती जा रही है।

मतदाता क्या कहता है: बिहार 2020 सर्वेक्षण से मुद्दा-प्राथमिकता और द्वंद्व

लोकनीति-सीएसडीएस के बिहार 2020 मतदानोत्तर सर्वेक्षण में जब मतदाताओं से पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में मतदान के समय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था, तो "विकास" 36.7% के साथ शीर्ष पर रहा और "बेरोज़गारी/नौकरी/भर्ती/उद्योग की कमी" 21.0% के साथ

© Copyright @ Authors

दूसरा बड़ा मुद्दा रहा [1]। महँगाई 10.9% और सरकार के काम/प्रदर्शन 6.4% जैसे उत्तर भी इसी विकास-केन्द्रित फ्रेम को विस्तार देते हैं [1]।

तालिका 4: बिहार 2020, मतदान के समय "सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा" (प्रतिशत)

मुद्दा	प्रतिशत
विकास	36.7
बेरोज़गारी/नौकरी/भर्ती/उद्योग	21.0
महँगाई	10.9
सरकार का काम/प्रदर्शन	6.4

स्रोत: लोकनीति-सीएसडीएस, बिहार 2020 मतदानोत्तर सर्वेक्षण [1]।

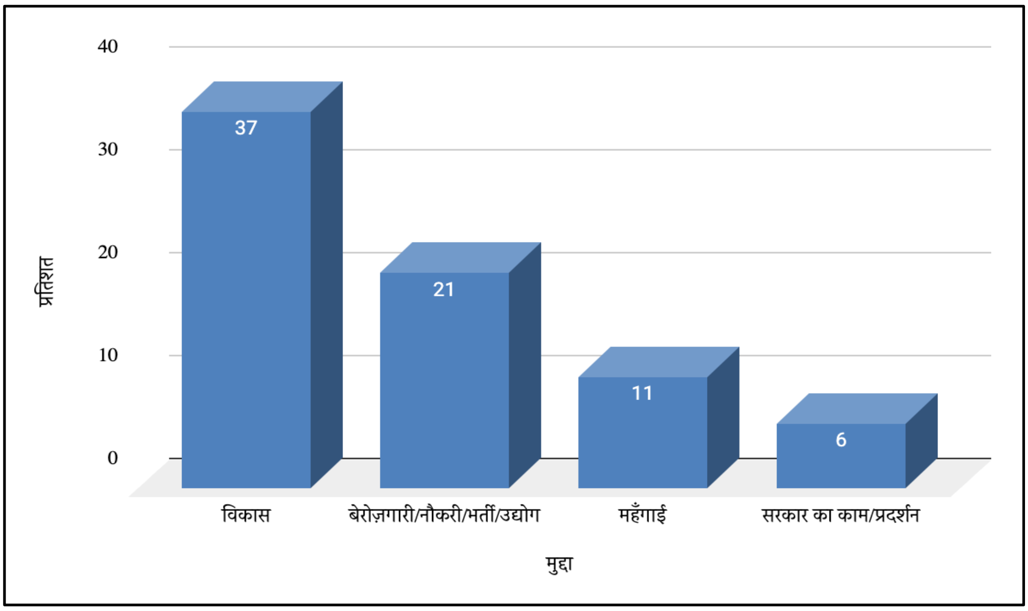

चित्र 3: बिहार 2020, मतदान के समय "सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा" दंड आरेख

यही सर्वेक्षण एक और निर्णायक प्रश्न पूछता है, जिसमें दो कथन रखे गए: पहला कि इस चुनाव में केवल सुशासन और विकास ही सबसे बड़े मुद्दे थे; दूसरा कि सुशासन-विकास ठीक है, पर असली मुद्दा जाति और समुदाय का था। इस द्विविकल्प में 67.1% ने पहले कथन से सहमति और 25.5% ने दूसरे कथन से सहमति व्यक्त की [1]। यह निष्कर्ष छपरा जैसे क्षेत्र में विकास-विमर्श के उभार को समझने के लिए सीधा अनुभवजन्य आधार देता है, हालांकि इसे "जाति का अंत" कहकर पढ़ना सही नहीं होगा। यह अधिक सटीक रूप से बताता है कि मतदाता अपने निर्णय

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

को वैध ठहराने की भाषा में विकास/सुशासन को प्रमुख तर्क मानने लगा है, जबकि पहचान का प्रभाव अक्सर "पृष्ठभूमि संरचना" के रूप में काम करता है।

तालिका 5: बिहार 2020—"सुशासन-विकास" बनाम "जाति-समुदाय" (प्रतिशत)

कथन	प्रतिशत
केवल सुशासन और विकास सबसे बड़ा मुद्दा	67.1
असली मुद्दा जाति और समुदाय	25.5

स्रोत: लोकनीति-सीएसडीएस, बिहार 2020 मतदानोत्तर सर्वेक्षण [1]।

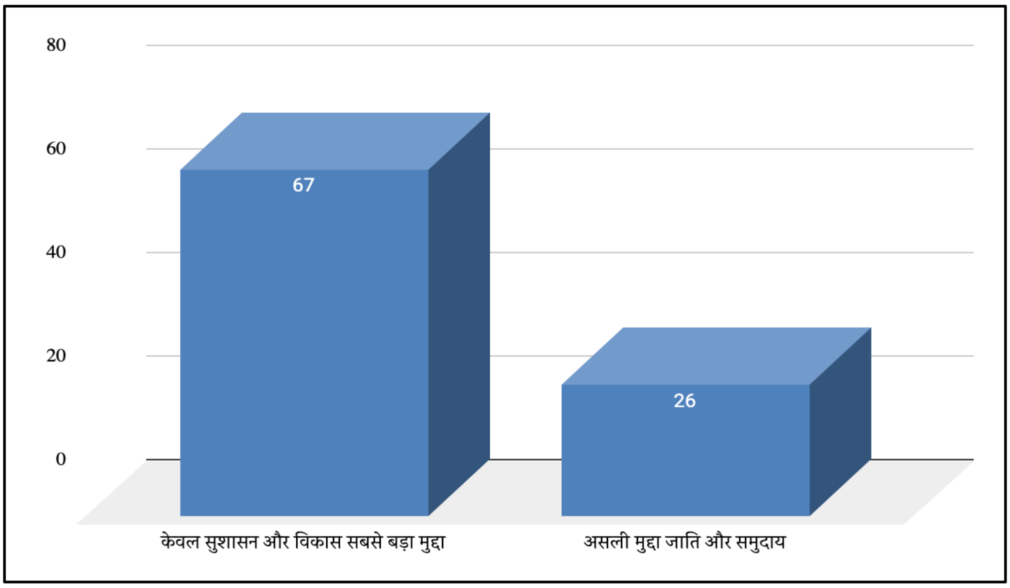

चित्र 4: बिहार 2020—"सुशासन-विकास" बनाम "जाति-समुदाय" दंड आरेख

इन निष्कर्षों की पद्धति-सूचना भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वेक्षण 29 अक्टूबर से 9 नवंबर 2020 के बीच 3,612 मतदाताओं पर बहु-चरणीय यादृच्छिक नमूना पद्धति से किया गया बताया गया है [10]। इससे निष्कर्षों को "संदर्भ-समझ" के साथ छपरा-सारण के विश्लेषण में जोड़ा जा सकता है।

विकास-विमर्श क्यों बढ़ा: कल्याण, सेवाएँ, और रोजगार-आकांक्षा की राजनीति

छपरा में विकास-विमर्श के उभार को तीन परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं से समझा जा सकता है। पहली प्रक्रिया कल्याणकारी योजनाओं और सेवा-वितरण का विस्तारण है, जिसने मतदाता को राज्य के साथ प्रत्यक्ष "लेन-देन" संबंध में बाँधा। जब राशन, आवास, स्वच्छता, या बिजली जैसी सेवाएँ दैनिक जीवन की सुरक्षा बनती हैं, तब मतदाता राजनीतिक प्रदर्शन को मापने लगता है। एनएफएचएस-5 के व्यापक संकेतक-सारांश में बिजली, बेहतर पेयजल स्रोत और स्वच्छता

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

सुविधा तक पहुँच बढ़ने जैसी प्रवृत्तियों की चर्चा मिलती है, जो "विकास की अनुभूति" का आधार बनती हैं [12]। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के हिंदी संस्करण में भी आधारभूत संरचना, ऊर्जा, डिजिटल शासन और महिला स्व-सहायता समूहों के प्रसार जैसी प्रवृत्तियों का उल्लेख मिलता है, जो राजनीतिक बहस में "काम" और "लाभ" के रूप में रूपांतरित होते हैं [11]।

दूसरी प्रक्रिया रोजगार-आकांक्षा का तीव्र होना है। राष्ट्रीय स्तर पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्टें रोजगार-अनिश्चितता, श्रमबल सहभागिता, और रोजगार की गुणवत्ता जैसे मुद्दों को नीति-चर्चा का केन्द्र बनाती हैं [9]। जब यही मुद्दा बिहार 2020 में 21.0% के साथ "सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा" के रूप में उभरता है, तो छपरा जैसे क्षेत्र में प्रवासन, प्रतियोगी परीक्षाएँ, और भर्ती-राजनीति का प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है [1]।

तीसरी प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा की संरचना है। छपरा विधानसभा 2020 में 6,771 मत का अंतर और सारण लोकसभा 2024 में 13,661 मत का अंतर यह दिखाता है कि चुनाव अब "मार्जिन-राजनीति" की ओर बढ़ रहा है, जहाँ एक ही सामाजिक समूह के भीतर विकास-प्रदर्शन, उम्मीदवार-छवि और स्थानीय मुद्दे निर्णायक हो सकते हैं [2], [3]। इस प्रतिस्पर्धा में पहचान-राजनीति अपनी जगह बनाए रखती है, पर वह अधिक बार "किसे अवसर दिया, किसका प्रतिनिधित्व हुआ" के साथ "किसने काम कराया" से जुड़ जाती है।

चर्चा

छपरा में मतदान-निर्णय का बदलता आधार वस्तुतः "जाति से विकास की ओर एक सीधी रेखा" नहीं है, बल्कि पहचान और विकास के पुनर्संयोजन की प्रक्रिया है। पहचान यहाँ भी कार्‌य करती है, क्योंकि सामाजिक नेटवर्क अभी भी राजनीतिक संचार, उम्मीदवार-विश्वसनीयता, और सामूहिक अपेक्षा का माध्यम हैं [6], [7]। परंतु विकास-विमर्श अब पहचान-आधारित राजनीति पर एक प्रकार का "परफॉर्मेंस फिल्टर" लगा देता है। उदाहरणतः किसी समूह का मतदाता अपने पारंपरिक राजनीतिक झुकाव के भीतर रहकर भी यह पूछता है कि उसके क्षेत्र में सड़क, विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधा, या रोजगार अवसरों के संदर्भ में क्या बदला।

लोकनीति-सीएसडीएस के निष्कर्ष कि 67.1% मतदाता "केवल सुशासन-विकास" को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, इस बात का सामाजिक प्रमाण है कि विकास-विमर्श अब राजनीतिक वैधता का प्रमुख नैरेटिव बन गया है [1]। साथ ही, 25.5% का "जाति-समुदाय" को असली मुद्दा मानना यह भी बताता है कि पहचान का आधार समाप्त नहीं हुआ है [1]। इसीलिए छपरा के चुनावी व्यवहार को समझने का बेहतर तरीका यह है कि पहचान और विकास को प्रतिस्पर्धी श्रेणियों की बजाय "परतों" के रूप में देखा जाए—जहाँ पहचान एक स्थायी सामाजिक संरचना देती है, और विकास उस संरचना के भीतर निर्णय के निकटवर्ती कारण बनता है।

इस संदर्भ में उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि और पारदर्शिता का प्रश्न भी निर्णय-तर्क का हिस्सा बनता है। उम्मीदवारों के हलफनामों पर आधारित सूचना-प्रणालियाँ मतदाता के सामने आपराधिक मामलों और संपत्ति जैसी जानकारियाँ रखती हैं, जो "सुशासन" और "विश्वसनीयता"

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

के विमर्श को स्थानीय स्तर पर ठोस बनाती हैं [13]। ऐसी सूचनाएँ पहचान के पारंपरिक तर्क के साथ मिलकर एक नया निर्णय-रसायन बनाती हैं, जहाँ "हमारा" उम्मीदवार भी अब "कितना सक्षम/विश्वसनीय" के मानक पर आंका जा सकता है।

निष्कर्ष

छपरा में मतदान-निर्णय के बदलते आधार का निष्कर्ष यह नहीं है कि जाति पहचान अप्रासंगिक हो गई है। अधिक सटीक निष्कर्ष यह है कि पहचान-आधारित राजनीतिक संरचना के भीतर विकास-विमर्श, सेवा-वितरण का अनुभव, और रोजगार-आकांक्षा, ये निर्णायक निकटवर्ती कारक के रूप में उभरे हैं। छपरा विधानसभा 2020 और सारण लोकसभा 2024 की संकीर्ण जीत-हारें यह दिखाती हैं कि चुनाव अब सीमांत बदलावों से तय होते हैं; ऐसे में विकास-प्रदर्शन, स्थानीय मुद्दे, और कल्याणकारी पहुँच "स्विंग" का निर्माण करते हैं [2], [3]। लोकनीति-सीएसडीएस के सर्वेक्षण निष्कर्ष छपरा-सारण जैसे क्षेत्र में विकास/सुशासन को मतदाता की निर्णय-भाषा में केंद्रीय स्थान देते हैं, जबकि जाति-समुदाय की भूमिका पृष्ठभूमि संरचना के रूप में बनी रहती है [1], [10]। सारण जिला प्रशासन के जनसांख्यिकी और शिक्षा संकेतक यह स्पष्ट करते हैं कि विकास-विमर्श का सामाजिक आधार साक्षरता, जनघनत्व, और सेवा-आवश्यकताओं के साथ गहरे रूप से जुड़ा है [4], [5]।

अतः छपरा में "जाति पहचान से विकास विमर्श तक" का अर्थ एक रैखिक संक्रमण नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक निर्णय-तर्क का पुनर्गठन है—जहाँ पहचान, प्रदर्शन और आकांक्षा एक साथ मिलकर मतदान को आकार देते हैं।

सन्दर्भ

1. लोकनीति-सीएसडीएस, "बिहार मतदानोत्तर सर्वेक्षण 2020: सर्वेक्षण निष्कर्ष," पीडीएफ प्रतिवेदन, 2020, पृ. 3–4, पृ. 18–19।
2. भारत निर्वाचन आयोग, "बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020: निर्वाचन क्षेत्र-वार विस्तृत परिणाम (छपरा)," आधिकारिक सांख्यिकीय प्रतिवेदन, 2020, पृ. 62।
3. भारत निर्वाचन आयोग, "लोकसभा आम चुनाव 2024: निर्वाचन क्षेत्र-वार विस्तृत परिणाम (सारण)," आधिकारिक सांख्यिकीय प्रतिवेदन, 2024, पृ. 66–67।
4. जिला प्रशासन सारण, "जनसांख्यिकी (जनगणना 2011 आधारित)," आधिकारिक वेबसाइट, अद्यतन 2026।
5. जिला प्रशासन सारण, "शिक्षा: जिला-स्तरीय संकेतक," आधिकारिक वेबसाइट, 2026।
6. के. चंद्रा, व्हाइ एथनिक पार्टीज़ सक्सीड: पैट्रनैज ऐंड एथनिक हेडकाउंट्स इन इंडिया. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004, पृ. 1–264।

© Copyright @ Authors

7. सी. जाफ़्रेलो, इंडियाज़ साइलेंट रेवोल्यूशन: द राइज़ ऑफ़ द लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडिया. नई दिल्ली: पर्मानेंट ब्लैक, 2003, पृ. 467–503 (मुद्रित संस्करण-आधारित कुल पृष्ठ)।
8. पी. चिब्बर और आर. वर्मा, आइडियोलॉजी ऐंड आइडेंटिटी: द चेंजिंग पार्टी सिस्टम ऑफ़ इंडिया. नई दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2018, पृ. 135–256।
9. भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, "आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: वार्षिक रिपोर्ट 2023–24," 2024।
10. लोकनीति-सीएसडीएस, "बिहार मतदानोत्तर सर्वेक्षण 2020: पद्धति-सूचना," पीडीएफ, 2020, पृ. 1–2।
11. बिहार सरकार, "आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 (हिंदी संस्करण)," आधिकारिक पीडीएफ, 2025।
12. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, "राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5: प्रमुख संकेतक (सारांश)," 2021।
13. एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स, "छपरा (सारण) बिहार 2020: उम्मीदवारों के हलफनामों पर आधारित प्रोफ़ाइल," माईनेता पोर्टल, 2020।

© Copyright @ Authors